all stages of education, they are still high due to socio-economic and pedagogic reasons.

(c) and (d) There have been several initiatives, details of which are available in the Annual Reports of the Ministry. Efforts have been continuously made to improve the content and process of education and make learning joyful and child centred. Recently, a major initiative has been launched by Central Government in the form of National Programme of Nutritional Support to Primary Education with a view to improve attendance in primary schools.

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

- 1974. श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या देश के प्रमुख उर्वरक एककों के बन्द हो जाने से उर्वरकों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;
- (ख) क्या सरकार ने इस स्थित से निपटने के लिए उर्वरकों का आयात करने का निर्णय किया है;
 - (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन एककों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार उर्वरकों पर राज-सहायता बन्द करने का विचार रखती है?

रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) और (ख) एफ सी आई का गोरखपुर एकक तथा एच एफ सी के नामरूप एकक का अमोनियम सल्फेट संयंत्र क्रमशः जून, 1990 तथा जुलाई, 1992 से बन्द पड़ा है। इसके अलावा एच एफ सी की हिल्दया परियोजना, जो नवम्बर, 1979 में यांत्रिक रूप से पूर्ण हो चुकी थी, इसके आरम्भण के दौरान से बारम्बार उपस्कर खराबियों के कारण उसमें वाणिज्यिक प्रचालन नहीं किया जा सका। परियोजना के प्रारम्भण कार्यकलाप अक्तूबर, 1986 से अन्तिम रूप से बन्द पड़े थे।

इन एककों के बन्द होने से उर्वरकों के मूल्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था।

- (ग) और (घ) स्वदेशी उपलब्धता तथा मूल्यांकित मांग के बीच के अन्तर को यूरिया के आयात से पूरा किया जाता है।
 - (ङ) जी, नहीं।

Steps Taken in Launching of Mid-daymeals

1975. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the steps that have been taken in different States and Union Territories in pursuance of the Mid-Day-Meal Scheme launched by the Prime Minister on independence Day this year;
- (b) the average cost per child per day incurred on the Mid-Day-Meal Scheme in different States and Union Territories; and
- (c) the calorie value of such food per child per day in each State/Union Territory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU (a) Under BHOI): the National Programme of Nutritional Support to Primary Education, foodgrains have been released through FCI to all States/Union Territories for distribution of serving cooked meals to all children studying in primary Government, classes in Government aided and local body schools located in identified blocks. Reports have been received from all States and Union that implementation Territories begun.

- (b) the average cost varies from State to State. The approximate cost of the cereals given by the Central Government is Rs. 0.70 per child per day.
- (c) The calorific values vary widely because of the variations in the modes of delivery. However, the calorific value of 100 grams of cereals being supplied by

Government of India is about 340 calories.

शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उपलब्ध सुविधायें

1976. श्री संघ प्रिय गौतमः क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को क्या-क्या सुविधार्ये दी जा रही हैं: और
- (ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर परदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां): कल्याण मंत्रालय अल्पसंख्यकों के लक्षित समूह के लिए भी आर्थिक मानदंडों के आधार पर परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा निःशुल्क वृत्तिका संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए काँरपस निधि के रूप में 30 करोड़ रुपए के एक मुश्त अनुदान के साथ सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विशेष तौर से अन्य पिछड़ें वर्गों में शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ावा देता है। यह प्रतिष्ठान नौकरियों तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में तैयार किए गए कार्रवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए तीन अलग योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र गहन कार्यक्रम मदरसा शिक्षा तथा समुदाय पौलीटेक्रीक का आधुनिकीकरण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेओं के माध्यम से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए कोचिंग योजना को कार्यान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोचिंग योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों को निःशुल्क वृत्तिका संबंधी कोचिंग प्रदान की जाती है।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वार क्षेत्र गहन कार्यक्रम के अंतर्गत 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को 83.51 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

. दुधारू पशुओं की दूध क्षमता

1977. श्री ईश दत्त यादवः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) वर्ष 1990-91 और 1994-95 के दौरान प्रत्येक दुधारू प्रत्येक पशु की दूध क्षमता कितनी थी;
- (ख) वर्ष 1996-97 के बाद दूध क्षमता में वृद्धि करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;
- (ग) क्या देश में दूध उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने हेतु दुधारू पशुओं की नस्त में सुधार करने के लिए अनेक अनुसंधान किए गए हैं;
- (घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से अब तक इस संबंध में क्या-क्या अनुसंधान कार्य किए गए हैं और इनके परिणामस्वरूप पशुओं की दूध देने की क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है;
- (ङ) क्या इन अनुसंधानों का उपयोग ग्रामीणों के लिए सुलभ बनाने हेतु कोई व्यवस्था की गई है;
 - (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
 - (छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरिवंद नेताम): (क) से (छ) 1990-91 तथा 1993-94 के दौरान प्रति पशु प्रति दिन औसत दूध की पैदावार नीचे दी गई है। 1994-95 के नमूना सर्वेक्षण के परिणामों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है:—

	प्रति पशु प्रति दिन औसत दूध की पै दावार (कि॰प्रा॰)			प्रतिशत वृद्धि
	1990-9	1 19	93-94	
गाय	1.91	2.43	(अनन्तिम)	27.2
भैस	3.41	3.78	(अनन्तिम)	10.8

1996-97 के बाद प्रति दुधारू पशु के औसत दुग्ध पैदावार की दर का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास गोपशु